

20 फरवरी को "डैडलाइन" से पहले बच्चे को अमेरिका में जन्म देने के लिये दौड़ लगी

इस दौड़ में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय गर्भवती महिलाओं की है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के जन्म आधारित नागरिक अधिकार खत्म करने के कार्यकारी आदेश के बाद, अमेरिका के दम्पतियों, जो माता-पिता बनने वाले हैं, में 20 फरवरी से पहले सी सेशन से बच्चे को जन्म देने की होड़ लग गई है। ट्रम्प ने 20 फरवरी को डैडलाइन दी है जन्म आधारित नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने के लिए।

इन मामलों में से अधिकांश भारत के हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह चलन दक्षिण एशियाई देशों के अलावा अन्य देशों में भी है, क्योंकि हरेक व्यक्ति मामूली सी संभावना होने पर इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है।

ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा बच्चे को होगा, क्योंकि जो महिलाएं सी सेशन का विकल्प चुन रही हैं, वे गर्भावस्था में आठवें या नवें महीने में हैं। गर्भावस्था की अवधि पूरी होने में कुछ ही समय बचता है, पर इससे बच्चे को खतरा हो सकता है।

न्यूजर्सी की मैटरनिटी क्लीनिक में कार्यरत डॉ. एस.डी. रामाराव ने कहा कि

ये महिलाएं, जिन्हें गर्भ धारण किये आठ या नौ महीने ही हुए हैं, "डैडलाइन" से पहले बच्चे को अमेरिका में जन्म देने के लिये, अमेरिका में डॉक्टरों पर "सिज़ेरियन" प्रक्रिया से बच्चे को जन्म देने के लिए दबाव डाल रही हैं। हालांकि, डॉक्टर उन्हें बार-बार सलाह दे रहे हैं कि इस प्रक्रिया से बच्चे की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

समय से पूर्व जन्मे ऐसे बच्चों में फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। इन बच्चों को माँ का स्तनपाक करने में भी कठिनाई होती है। इन बच्चों का जन्म के समय वजन भी बहुत कम होता है तथा कुछ बच्चों में "न्यूरोलॉजिकल प्रॉबलम्स" भी विकसित हो जाती हैं।

ट्रम्प द्वारा निर्धारित डैडलाइन का उन लाखों भारतीयों पर असर पड़ेगा, जो अमेरिका में अस्थायी वीजा प्राप्त करके रह रहे हैं।

क्योंकि, अमेरिका में "ग्रीन कार्ड" प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, उन भारतीय दम्पतियों के लिए यह एक "सेप्टी नेट" है, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं और उनकी पत्नियों गर्भवती हैं।

उन्से समय से पूर्व डिलीवरी कराने के लिए कई लोगों ने आग्रह किया है। एक महिला का मार्च में बच्चा होना है, वह सात माह की गर्भवती है, पर अपने पति

के साथ समय से पहले डिलीवरी के लिए आई थी।

अस्थायी रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों में जन्म आधारित नागरिकता के अधिकार की डैडलाइन 20 फरवरी से पहले बच्चों को जन्म देने की होड़ लगी है, ताकि बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए।

जन्म के आधार पर स्वतः नागरिकता मिल जाने के अधिकार को खत्म करना इमिग्रेशन नीति में बड़ा बदलाव है तथा इससे अमेरिका में अस्थायी वीसा पर रह रहे लाखों भारतीय प्रभावित होंगे।

जन्म आधारित नागरिकता एक कानूनी सिद्धांत है, जो अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को अमेरिका का नागरिक बनने का अधिकार देता है, भले ही उसके माता-पिता किसी भी देश के हों और उनकी इमिग्रेशन स्थिति चाहे जो हो।

डॉ. एस.जी. मुक्काला ने लोगों को समय पूर्व प्रसव के सम्बंध में चेतावनी दी और कहा कि ऐसे बच्चों के फेफड़े विकसित नहीं हो पाते हैं, उन्हें फीडिंग में समस्या होती है, उनका वजन कम होता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीमकाथाना व गंगापुर सिटी जिला समाप्ति मामले की सुनवाई 28 जनवरी को

जयपुर, 23 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने नव सुजित नीमकाथाना जिले का दर्जा समाप्त करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही, अदालत ने इस मामले को समान प्रकरण में गंगापुर सिटी के मामले में रामकेश मीणा की ओर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को सुचीबद्ध करने को कहा है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक रमेश चंद्र खंडेलवाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए वही, मामले में नीमकाथाना बार

हाई कोर्ट में सरकार की ओर से इस मामले में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने पैंटी की।

एसोसिएशन की ओर से भी याचिका पेश की गई है।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पेश हुए। उनकी ओर से याचिका में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर खंडपीठ ने याचिका को रामकेश मीणा की याचिका के साथ सुचीबद्ध करने को कहा है। याचिका में अधिवक्ता निखिल सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने रामलुभाया कमेटी की सिफारिशों और तय मापदंडों के आधार पर नीम का थाना सहित, अन्य जिलों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हम हमेशा, "बिना कागज़ात" अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को वापस भारत भेजने के पक्ष में रहे हैं'

विदेश मंत्री जयशंकर को ट्रम्प प्रशासन के लगातार दबाव के कारण प्रैस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से कहना ही पड़ा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। अवैध प्रवासियों, जिनमें कई भारतीय भी हैं, के खिलाफ ट्रम्प सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों के बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि उनका देश अनाधिकृत भारतीयों की वापसी के लिए खुला है।

हालांकि यह सच है कि भारत ने अवैध रूप से विदेश, खासकर अमेरिका, जाने वाले भारतीयों के खिलाफ कभी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। भारतीयों में अमेरिका के प्रति बेहद रूढ़ान है, जिसे अधिकांश लोग सोने की खान मानते हैं।

जयशंकर के पास यह कहने के सिवा कोई चारा नहीं था कि भारत में उन लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें अमेरिका से निर्वासित किया जा सकता है, अभी इनकी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है।

भारतीयों का रुस की सेना में शामिल होना, हमास के खिलाफ इजरायल की सेना के साथ लड़ना, इस बात का सबूत है कि भारत में बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। लेकिन सरकार इस

पर, यह भी सच है कि अभी तक, आज तक, भारत सरकार ने भारत से अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से जाने वाले भारतीयों को रोकने का कोई गंभीर प्रयास भी नहीं किया।

भारत में भारी बेरोजगारी के कारण देश के मध्यम वर्ग या लोअर मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे, दलालों को पैसा देकर, विदेश (अमेरिका) जाने का निरन्तर प्रयास करते रहते हैं।

बेरोजगारी के ही कारण भारतीय युवक रूस की सेना में और हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए इजरायल सेना में भर्ती हुए।

पर, जब अमेरिका का वीजा प्राप्त करने में 400 दिन लगते हैं तो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाकर नौकरी करने के इच्छुक नौजवानों को कैसे रोका जा सकता है।

विदेश मंत्री ने इस तर्क के प्रति अमेरिका के विदेश मंत्री (संक्रैटरी ऑफ स्टेट) मार्को रुबिओ ने भी सहमति जताई।

प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जहाँ अमीर लोग दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, इनमें से कई तो छोटे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय व निम्न मध्यम वर्गीय युवा गैर कानूनी तरीकों से अलग-अलग देशों में जाने का प्रयास (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आप अपने लिए भाजपा से बड़ा खतरा कांग्रेस को मानती है

आप को डर है कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक वोट बैंक को खंडित ना कर दे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। आम आदमी पार्टी सार्वजनिक रूप से यह दावा भले ही कर रही हो कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि दिल्ली में करीब 10 सीटें ऐसी हैं, जहाँ आप, कांग्रेस पार्टी के प्रचार-अभियान पर खास नज़र रखे हुये हैं।

पिछले दो सप्ताह से, आप नेता दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस को "अप्रासंगिक" बता रहे हैं तथा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के साथ इसकी "मिलीभगत" है।

आम आदमी पार्टी, अन्य सीटों के अलावा, ओखला, चाँदनी चौक तथा बादली सीटों पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर मानकर चल रही है।

जहाँ ओखला में पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ अहमद खान की बेटी अरीबा खान आप के अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मैदान में हैं, वहीं

दिल्ली की दस विधानसभा सीटों पर आप कांग्रेस के प्रचार अभियान पर पैनी नज़र रखे हुए हैं।

इन दस सीटों में से तीन, ओखला, चाँदनी चौक और बादली में तो आप, कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना से चिंतित है।

चाँदनी चौक सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जे.पी. अग्रवाल के पुत्र मुदित अग्रवाल, आप के पुनर्दीप सिंह साहनी के खिलाफ खड़े हैं, जो चाँदनी चौक से वर्तमान विधायक प्रहलाद सिंह साहनी के पुत्र हैं। बादली सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव, आप के अजेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

आप के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "हमारे लिये, चिन्ता का विषय यह नहीं है कि कांग्रेस सीटें जीतेगी, बल्कि चिन्ता का विषय यह है कि स्वयं तो हार जायेगी, लेकिन भाजपा को अपनी स्थिति मजबूत करने में जरूर मदद करेगी।" उन्होंने कहा, "भाजपा पिछले

27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है तथा यह चुनाव उसके लिये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ने से भाजपा की ही मदद होगी।"

आप के एक अरुन्धी व्यक्ति ने कहा, "देखिये, 2017 के एमसीडी चुनावों में क्या हुआ था। केवल दो साल पहले, आप ने विधानसभा चुनाव 54 प्रतिशत के विशाल वोट-शेयर के साथ जीते थे तथा कांग्रेस केवल 10 प्रतिशत वोट ही पा सकी थी। लेकिन कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव अच्छी तरह लड़े। (नतीजा यह हुआ कि) आप का वोट शेयर गिरकर 26 प्रतिशत पर आ गया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य के 5897 गाँव अभावग्रस्त घोषित

जयपुर, 23 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए खरीफ बाढ़ एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ से कृषि आदान अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 20 जिलों के 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल खराबे वाले 5897 गाँव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से

मुख्यमंत्री भजनलाल ने बाढ़ व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि आदान अनुदान वितरण की स्वीकृति दी।

प्रभावित किसानों को बड़ा संबल मिलेगा। इस निर्णय के उपरान्त, अब आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने मानसून वर्ष 2024 (संवत् 2081) में बाढ़ और ओलावृष्टि से खरीफ फसलों के खराबे के आकलन के लिए गिरदावरी के निर्देश दिए थे और जिला कलक्टरों से प्राप्त नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में व्याप्त गंदगी के लिए केजरीवाल पर कटाक्ष किया, योगी आदित्यनाथ ने

क्या केजरीवाल व उनकी सरकार के लोग यमुना में डुबकी लगाने को तैयार हैं?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में यमुना नदी में लाखों लोगों के स्नान करने का श्रेय लेते हुये, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविन्द केजरीवाल पर तंज करते हुये, उनसे तथा उनके मंत्रियों से पूछा कि क्या वे लोग दिल्ली में प्रदूषित यमुना में स्नान करने की हिम्मत कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दिल्ली में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया तथा मतदाताओं से आसन्न दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा को समर्थन देने का अनुरोध किया। योगी ने जनसभा में उपस्थित भारी भीड़ से विकास, कानून-व्यवस्था में सुधार तथा भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन का वादा किया। दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर की बिगड़ती हुई स्थिति का हवाला देते हुये, उन्होंने कहा, "यह राष्ट्रीय राजधानी है।

जैसा कि विदित है कि महाकुंभ के अवसर पर योगी व उनके मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई थी, जो बहुत प्रचारित रही थी।

योगी ने दिल्ली और समीपवर्ती गाज़ियाबाद, जो उत्तर प्रदेश का शहर है, की तुलना की और कहा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा, आप सरकार दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाई।

एन.डी.एस.सी. क्षेत्र के अलावा, दिल्ली की सड़कों, जल-आपूर्ति तथा बिजली की हालत देखिये। एक दशक पहले, यहाँ लोग बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैट्रो सेवा तथा सफाई के कारण आया करते थे। लेकिन अब, इस सरकार ने इसकी कैसी हालत कर दी है। सड़कों में गड्डों की भरमार है तथा कुछ स्थानों पर तो यह बताना मुश्किल है कि क्या गड्डों में कहीं सड़क है। हर जगह कूड़ा-करकट तथा धूल-मिट्टी दिखाई देती है।"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप सरकार पर प्रहार करते हुये, उस पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है तथा पेयजल संकट है। आप सरकार इन मूलभूत मुद्दों के समाधान में असफल रही है।"

आप नेतृत्व की आलोचना करते हुये, आदित्यनाथ ने उस पर वास्तविक स्थिति की तुलना में सोशल मीडिया को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "जनता के लिये काम

करने के बजाय, आप नेता, जिनमें अरविन्द केजरीवाल भी शामिल हैं, अपना समय झूठे दवाब करने में गुजारते हैं। अगर उन्होंने ऐसे प्रयास प्रशासन के माामले किये होते, तो दिल्ली का कायापालट हो सकता था।"

दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की तुलना करते हुये आदित्यनाथ ने कहा, "दिल्ली और गाज़ियाबाद की सड़कों में सार्वजनिक सुविधाओं में जबरदस्त अन्तर है। आप ने दिल्लीवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया है।"

गुजर समय के विवादों का हवाला देते हुये, आदित्यनाथ ने कहा, "2020 में, दिल्ली शहर दंगों का साक्षी बना तथा (दंगों में) एक आप पापंद की लिफ्टता सामने आई। आप सरकार शान्ति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगातार असफल रही है।"

चेक बाउन्स केस में रामगोपाल वर्मा को तीन माह की जेल

मुंबई, 23 जनवरी। महाराष्ट्र में मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को चेक अनादरण (बाउन्स) मामले में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। एक वकील ने यहाँ गुरुवार को बताया कि वर्मा के खिलाफ सात साल पहले परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया

सात साल पुराने केस में अदालत ने तीन माह के भीतर 3.72 लाख का जुर्माना भरने के निर्देश दिए वरना 3 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी।

गया था। अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायालय में पेश न होने की वजह से न्यायालय को वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया। अदालत ने वर्मा को 3.72 लाख (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई

नई दिल्ली, 23 जनवरी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा ली गई है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देश पर पंजाब पुलिस के जवान जो केजरीवाल की

आप पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती केजरीवाल की सुरक्षा कम की।

सुरक्षा में तैनात थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। पंजाब के डीजीपी ने कहा कि केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं और इस वजह से दिल्ली पुलिस से जानकारी साझा कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। इस बीच संजय सिंह ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में अपने पहले दिन कई कार्यकारी आदेश जारी किए, उनमें से एक थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन (डब्ल्यू. एच.ओ.) से अमेरिका की निकासी की घोषणा। यह निकासी, जो एक वर्ष बाद प्रभावी होगी, भारत पर कई सीधे और अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकती है। यह इस पर निर्भर करेगा कि ग्लोबल हेल्थ इकोसिस्टम इस बदलाव के साथ कैसे एडजस्ट करता है। अमेरिका का डब्ल्यू.एच.ओ. में

प्रमुख योगदान रहा है। इसकी निकासी से एक महत्वपूर्ण वित्तीय कमी उत्पन्न हो सकती है, जो विश्वभर में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकती है। भारत, जो पोलियो उन्मूलन, तपेदिक (टीबी) उन्मूलन और टीकाकरण अभियानों जैसी डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा संचालित पहलों का प्रमुख प्राप्तकर्ता है, को इन कार्यक्रमों में देरी या धन की कमी का सामना कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गान्धी (वैक्सिनेशन अलायंस) जैसी विशिष्ट पहल, जो डब्ल्यू.एच.ओ. प्रयासों से जुड़ी हुई है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो

जैसा कि विदित ही है, कोविड-19 के दौरान डब्ल्यू.एच.ओ. की गाइडलाइन्स, रिसर्च तथा सफ़ाई शृंखलाओं का नेटवर्क बहुत काम आया था, महामारी से जूझने में।

भारत को यूरोपियन यूनियन, चीन व रूस की ओर देखना होगा और अधिक सहयोग व अन्य मदद के लिये, अन्यथा, भारत के रिसोर्सिज़ व कूटनीतिक ऊर्जा पर भारी दबाव रहेगा, डब्ल्यू.एच.ओ. में अमेरिका की कमी को पूरी करने के लिए विकल्प ढूँढ़ने में।

संभव है और भारत के टीकाकरण प्रयासों पर असर डाल सकती है।

दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों को

डब्ल्यू.एच.ओ. से स्वास्थ्य संकटों के समाधान के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और समर्थन प्राप्त होता है। डब्ल्यू.एच.ओ. के कमज़ोर पड़ने से भारत की क्षेत्रीय हेल्थ लीडर की भूमिका प्रभावित होगी और हेल्थ एमरजेंसी के समय भारत को अपने पड़ोसी देशों की अधिक सक्रिय रूप से सहायता करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

अमेरिका की डब्ल्यू.एच.ओ. से निकासी से ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस में एक रिक्त स्थान पैदा होगा, जिसमें भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में अपनी भूमिका को मजबूत करना पड़

सकता है और यूरोपीय संघ, चीन और रूस जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के साथ मिलकर बहुपक्षीय सहयोग को बनाए रखने के लिए काम करना पड़ सकता है। इससे भारत की कूटनीतिक क्षमता और संसाधन प्रभावित हो सकते हैं।

डब्ल्यू.एच.ओ. के कमज़ोर होने से भारत को अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमताओं को बढ़ाना पड़ सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि भारत को, ग्लोबल फंड या गेट्स फाउंडेशन जैसे अन्य ग्लोबल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

ईश्वर एक शाश्वत बालक है जो शाश्वत बाग में शाश्वत खेल खेल रहा है। -अरविन्द

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने के स्थान पर समाधान तलाशें

अरविन्द कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ केस नं. W.P.(C) 1246/2020 के केस में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करने जा रहा है:-

(1) क्या पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3 तथा 4 संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 तथा समानता के अधिकार को गांठती का उल्लंघन करती है?

(2) क्या धारा 2, 3 व 4 अनुच्छेद 25, 26, और 29 तथा संविधान में धर्म निरपेक्षता की मूल विशेषता का उल्लंघन करती है?

(3) क्या आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किये गये मंदिर हिन्दू तथा इस्लामी पर्सनल लॉ के तहत मंदिर बने रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकायें उपरोक्त विषयों पर सुनवाई हुई हैं। राजनीतिक दलों जिसमें आरजेडी, एएमआईएम, जमीयत उलेमा-ए-हिन्द आदि हैं उन्होंने अपनी-अपनी पिटाइनस में सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है कि माननीय कोर्ट उक्त पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों का समर्थन करे ताकि देश में सभी लोगों में समरसता व भाईचारा बना रहे और कोई साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न नहीं हो, तथा संविधान का धर्मनिरपेक्ष ताना बना सुरक्षित रहे। पूजा स्थल अधिनियम अथवा उपसमा स्थल अधिनियम 1991 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई सभी पिटाइनस को सुनवाई 2-3 होगी। इसे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है। केस में सुनवाई के हेतु 17 फरवरी 2025 की पेशी नियत है। अंग्रेजी में इस अधिनियम को प्लेसिज ऑफ वॉशिप एक्ट 1951 के नाम से पुकारा जाता है।

यह अधिनियम 18 सितम्बर, 1991 को संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम बाबरी मस्जिद के विध्वंस से एक साल पूर्व सन 1991 में लाया गया था। बाबरी मस्जिद के (खंडहर) को 1992 में गिराया गया था। अधिनियम का पूरा नाम पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 है। इस कानून को संसद में किसी भी पूजा स्थल के धर्मनिरपेक्ष पर रोक लगाने और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाये रखने के अधिनियम (उद्देश्य) से पारित किया गया था, जो जैसा भी 15 अगस्त, 1947 को था। सर्वोच्च न्यायालय उपसमा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता पर निर्णय करेगा। यह कानून जैसा ऊपर कहा है उपसमा स्थलों के धार्मिक स्वरूप के बदलने से, जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, को रोकता है।

यह अधिनियम उस समय जन्ता के ध्यान में आया जब सर्वोच्च न्यायालय उस स्थान के सम्पत्ति विवाद का फैसला कर रहा था, जहां कभी बाबरी मस्जिद थी। मस्जिद के खंडहर को, जिस रूप में वह उस समय थी, कार सर्वेक्षण से 6.12.1991 को तोड़ा था। स्थिति कोर्ट में सम्पत्ति का विवाद वर्षों तक चला था। दावे के अनुसार इस को सम्पत्ति का मालिकाना हक हिन्दुओं के देवता भगवान श्रीराम (रामलला) विराजमान का माना था। दिनांक 9 नवम्बर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 5 न्यायाधीशों ने उक्त सम्पत्ति का अधिकार माना था। इस प्रकार 450 साल पुराने विवाद का अन्त हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को वैधता को सुरक्षित रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा "पूजा स्थल अधिनियम आन्तरिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के दायित्वों से संबंधित है यह सभी धर्मों की समानता के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" अरविन्द कुमार उपाध्याय को याचिका में उक्त एक्ट की धारा 2, 3 व 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

पूजा स्थल अधिनियम 1991 के मुख्य प्रावधानों को समझना प्रत्येक देश के नागरिक के लिये आवश्यक है। उपसमा स्थल अधिनियम, 1991 के अनुसार किसी भी उपसमा स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहना चाहिये जैसा वह 15 अगस्त 1947 को था। इसका उद्देश्य भी यही है कि पूजा स्थल के कथित ऐतिहासिक रूपान्तरण से उत्पन्न सभी विवादों को समाप्त करना है। धारा 3 स्पष्ट रूप से यह निर्देश देती है कि किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय के पूजा स्थल को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य धार्मिक सम्प्रदाय के पूजा स्थल में परिवर्तित करने की मनाही है यानी परिवर्तन करने पर रोक है और रोक की स्थिति यह है कि उसी धार्मिक सम्प्रदाय के किसी अन्य भाग के पूजा स्थल में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 4(1) के अनुसार 15 अगस्त 1947 को था धारा 4(2) में बतलाया गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपसमा स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के बावत किसी भी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लिम्बत कोई भी वाद या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जावेगी और कोई नया वाद या कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो सकेगी। यदि 15 अगस्त 1947 के बाद इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी उपसमा स्थल का धार्मिक स्वरूप बदल गया है और उससे संबंधित कोई वाद या अपील किसी न्यायालय में लिम्बत है तो उसका निर्णय धारा 4(1) अनुरूप ही किया जावेगा। धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम की कोई धारा राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले से संबंध किसी भी मुकदमे, अपील अथवा कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। धारा 6 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है।

कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे जैसे - (1) वे पूजा स्थल जो प्राचीन स्मारक व पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा संरक्षित हैं। (2) यदि कोई वाद इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही अन्तिम रूप से निपटारा जा चुका है तो यह अधिनियम लागू नहीं होगा। (3) उस स्थिति में भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा जहां विवाद जिसे इस अधिनियम के लागू होने के पहले ही दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से सेंटल किया जा चुका है।

कबीर हिन्दू व मुसलमान दोनों के लिये पूजनीय थे। उन्होंने दोनों धर्मों के पाखण्ड पूर्ण व्यवहार पर करारी और तीखी चोट की थी। कबीर का मानना था कि हर इन्सान में ईश्वर का निवास होता है। उसे मंदिर-मस्जिद में ढूँढना सही नहीं है। ईश्वर न तो काबा में मिलेगा न काशी में बल्कि वह तो हर इन्सान में मिलेगा।

प्रक्रियात्मक साधन के रूप में किसी धार्मिक चरित्र का पता लगाना वस्तुतः इस अधिनियम (एक्ट) की धारा 3 व 4 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकता। कृष्ण ध्यान दें कि उक्त विचार किसी निर्णय का अंश नहीं है। यानी यह विवाद का विषय नहीं है। मधुरा एवं ज्ञान्यापी दोनों के विवादों में मस्जिद पक्ष के इस व्याख्या को चुनौती दी है। इसका यह अर्थ है कि उपरोक्त रिट याचिकाओं की बहस में यह प्रश्न उठाया जावेगा।

दिनांक 15 अगस्त 1947 भारत के लिये एक ऐतिहासिक व महत्व का दिन है, जब देश एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक और संप्रभु राज्य बना था, जहां कोई रायधर्म नहीं है और धर्मों को स्वतंत्र रूप से देखा जाता है और नागरिकों को अपने-2 धर्म के रिवाजों, पद्धतियों के अनुरूप पूजा, साधना, उपसमा करने का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्र, अलग-2 धर्मों के पूजा स्थलों के पूजा स्थलों की यथास्थिति स्थापित रखने के लिये 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल एक्ट लागू किया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि देश में आजादी के वक्त अर्थात् 15.08.1947 को जो पूजा स्थल किस स्थिति में थे, वे वैसा ही रहेंगे। पूजा स्थल अधिनियम सभी धार्मिक स्थलों पर लागू है चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का हो, उसे दूसरे धर्म के पूजा स्थलों में परिवर्तित नहीं कर सकेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने कई याचिकायें पेश हो रही थी, इसे देखकर न्यायालय ने मुद्दकर्म बाजो पर विराम लगा दिया है। सभी अदालतों को निर्देश दिया है कि जब तक अपेक्स कोर्ट में मामले लिम्बत है तब तक अदालतें धार्मिक स्थलों के दावों के नये मुकदमें दर्ज नहीं करेंगे अथवा फाइनल आदेश पारित करेगी। सर्वे का भी आदेश नहीं देगी। पूजा स्थलों का विवाद संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 के तहत हल किया जाना चाहिये।

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने हिन्दू याचिकाकर्तों द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुये अपेक्स कोर्ट में प्ली ली थी कि अधिनियम के विरुद्ध याचिकाओं पर विचार करने से भारत में अनिश्चित मस्जिदों के विरुद्ध विवादों की बाढ़ आ जावेगी। इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी याचिकाओं का विरोध किया है।

जो याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हैं उनमें मुख्य तर्क यह है कि उक्त अधिनियम 1991 न्यायिक समीक्षा को रोकता है। धारा 4 न्यायालयों को विचारण मामले में निर्णय लेने से रोकती है। यह भी तर्क है और प्ली उठाई है कि चूंकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है और उसे खण्डित नहीं किया जा सकता अतः अधिनियम वैध नहीं है। उक्त अधिनियम धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त का भी उल्लंघन करता है। याचिका में एक्ट की वैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी है कि अधिनियम (एक्ट) एक धार्मिक समुदाय को वरीयता देता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 का भी अतिक्रमण करता है। आर्टिकल 14 व 15 के तहत समानता और भेदभाव के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 21 के तहत भी इसे चुनौती दी गई है, जिसका संबंध जीने के अधिकार से है। जैसा ऊपर कहा है कि अधिनियम अनुच्छेद 25, 26 व 29 के तहत दिये गये धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

एक याचिका में तर्क है कि चूंकि देवता शाश्वत होते हैं और मंदिर नष्ट करने के बाद भी मंदिर है, अतः मंदिर का स्वाभिम्व नष्ट नहीं होता।

वर्तमान में सर्वे से यह ज्ञात हुआ है कि हजारों मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ है। हिन्दुओं में जाग्रत आई है और वे तोड़े गये मंदिरों के स्थान पर पुनः मंदिरों को रेस्टोर (पुनः स्थापित) करना चाहते हैं। देश की अदालतें मंदिर/मस्जिद के विवादों से घिर जावेंगी और देश की संस्कृति और उसकी गंगा-जमुनी संस्कृति को भारी आघात होगा। सदभाव और भ्रातृ भाव में भारी तनाव पैदा होगा। अतः जो मुकदमें चल रहे हैं उनमें ऐसा निर्णय होना चाहिये जो राष्ट्रहित में हो। देश की एकता व अखण्डता अक्षुण्ण रहे। कुछ लोगों ने सलाह दी है कि हमें आपसी सदभाव से इन विवादों का हल निकालना होगा। यों तो मंदिर मंदिर में भेद नहीं हो सकता; किन्तु फिर भी भेद है और यह भी आस्था का प्रश्न है। मधुरा, काशी, सभल आदि कई स्थान के मंदिरों के विवाद आपसी सहमति से निपटारे जा सकते हैं। प्रयत्न करें कि विशिष्ट 12 मस्जिदों को अधिनियम की धारा 5 के तहत राम जन्मभूमि के मामले को तरह अपवाद में शामिल करें और शेष सभी मंदिरों के विवादों पर अधिनियम 1991 लागू किया जावे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के मंदिर मस्जिद के केस को बहुत ही कुशलता व राष्ट्र की एकता व अखण्डता के हेतु निर्णित किया है जिसे देश का महान इतिहास सदा याद करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि (बाबरी मस्जिद) केस में उक्त अधिनियम को विवेचना की है और उसे अपवाद किया जाने को वैध माना है।

पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाले तर्क सही हो सकते हैं और उस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है; किन्तु इससे राष्ट्र का अहित ही होगा, न्याय भी नहीं होगा। यदि देश के हिन्दू व मुसलमानों के मध्य कोई समझौता इस हेतु होता है तो वह चिर स्मरणीय होगा और इस घटना का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जावेगा।

कबीर व मुसलमान दोनों के लिये पूजनीय थे। उन्होंने दोनों धर्मों के पाखण्ड पूर्ण व्यवहार पर करारी और तीखी चोट की थी। कबीर का मानना था कि हर इन्सान में ईश्वर का निवास होता है। उसे मंदिर-मस्जिद में ढूँढना सही नहीं है। ईश्वर न तो काबा में मिलेगा न काशी में बल्कि वह तो हर इन्सान में मिलेगा। कबीर ने कहा था- "मोको कहाँ ढूँढे रे बन्दे मैं तो तेरे पास में।"

न मंदिर में न मस्जिद में, न काबा कैलाश में। कबीर ने कहा था, उसे पूजा स्थल में ढूँढना व्यर्थ है वह तो हर मनुष्य में है। हे, खुदा व ईश्वर के बन्दे कबीर के दर्शन व भागीय संविधान तथा संस्कृति को समझो और मंदिर-मस्जिद के इस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक गरिमा की छाया में आपसी सहमति से सुलझाने में इतिहास के साक्षी बने। सत्यमेव जयते।

-अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



राम शर्मा

हम वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था की चाल सकारात्मक रही। कई देशों में मंदी के बावजूद हमारी आर्थिक वृद्धि दर बनी रही। यूक्रेन-रूस युद्ध ने कुछ सेक्टर में महंगाई बढ़ाने का काम किया, लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था ने संतुलित विकास किया है। अब यह देखना रोचक होगा कि भारत के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा? भारत के लिए अपनी युवा जनसंख्या, डिजिटल तकनीक और मजबूत होते आधुनिक ढांचे से उम्मीद है कि यह वर्ष भी भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था: भविष्य की झलक

इस बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार न रहे।

भारत ने डिजिटल तकनीक के बुनियादी ढांचे में काफी प्रगति की है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से लाखों लोगों तकनीक का बेहतर उपयोग करने लगे हैं। 2025 तक, यह तकनीक लगभग हर क्षेत्र में जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त में केंद्रीय भूमिका निभाएगी। सरकार की कुत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देने की योजना, साथ ही साथ एक उभरते हुए स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेगा। फिनटेक, एडटेक और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ेंगे, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल का निर्माण करना है। 2017 में लागू किया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2025 तक कराधान प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम करेगा, जिससे व्यापार लागत घटेगी और अनुपालन में सुधार होगा।

भारत की शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जो अवसंरचना, आवास और परिवहन के लिए मांग को बढ़ावा देगी। स्मार्ट शहरों, मेट्रो रेल प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश से मजबूत आर्थिक विकास की नींव रखी जाएगी। वर्ष 2025 तक, भारत की अवसंरचना का विकास न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि उत्पादकता को भी बढ़ावा देगा, जिससे एक अधिक कुशल अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा।

भारत का वैश्विक व्यापार में स्थान तेजी से बढ़ रहा है। देश ने विशेष रूप से आईटी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्रों के निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी है। वर्ष 2025 तक, भारत वैश्विक निर्माण और सेवा केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। प्रमुख साझेदारों जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और दक्षिण-एशिया के

साथ व्यापार समझौतों से भारत की आर्थिक स्थिति वैश्विक बाजार में और मजबूत होगी।

इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। भारत में पर्याप्त श्रमशक्ति है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। हर हाथ को काम देना भारत के लिए इस वर्ष की बड़ी चुनौती होगी। कामकाजी उम्र की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन रोजगार बाजार जतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। इसके अलावा, श्रम कौशल अंतर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई श्रमिकों के पास उभरते हुए उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। वर्ष 2025 तक, सरकार और निजी क्षेत्र को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भारी निवेश करना आवश्यक होगा, ताकि एक ऐसे कार्यबल का निर्माण हो सके जो भविष्य के रोजगार के लिए तैयार हो। यदि भारत इन मुद्दों को हल नहीं करता है, तो युवा बेरोजगारी आर्थिक वृद्धि को बाधित कर सकती है।

आर्थिक असमानता को दूर करना देश की बड़ी समस्याओं में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसके लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, साथ ही विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समृद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। अमीर और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इस वर्ष में आय असमानता को दूर करना समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होगा। ऐसी नीतियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करें, असमानताओं को कम करें और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगी कि वृद्धि के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें।

भारत को गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे वायु प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन। देश का तेजी से औद्योगिकीकरण अक्सर उसके प्राकृतिक संसाधनों को कीमत पर हुआ है। वर्ष 2025 तक, भारत को सतत विकास पर अपने ध्यान को महत्वपूर्ण

रूप से बढ़ाना होगा, ताकि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और जलवायु संकट से निपटने में निवेश करना आवश्यक होगा। एक हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण भारत की घरेलू जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं दोनों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा।

कृषि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो देश की बड़ी जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। हालांकि, कृषि को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे निम्न उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और ऋण सेवाओं तक पहुंच प्रदान करनी होगी, ताकि शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन को रोक जा सके और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

भारत की अर्थव्यवस्था बाहरी तत्वों से प्रभावित हो सकती है, जिनमें वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध शामिल हैं। संरक्षणवाद, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव जैसे मुद्दे भारत के विकास की संभावनाओं के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। मजबूत कूटनीतिक उपस्थिति बनाए रखना और व्यापार संबंधों में विविधता लाना भारत को वैश्विक आर्थिक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इष्ट) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

भारत-पाक सीमा पर बी.एस.एफ. ने "ऑपरेशन सर्द हवा" शुरू किया

बीकानेर, (निर्स)। राजस्थान से सटी करीब 1000 किलोमीटर लंबी भारत-पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट (सर्द हवा) शुरू हो गया है। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि 26 जनवरी को देखते हुये दोनों पक्षों से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। इसे देखते हुये बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ऑपरेशन अलर्ट के तहत सेक्टर मुख्यालय से भी जवानों को सीमा पर तैनात किया गया है सभी बटालियन के अधिकारी भी सीमा पर पहुंच गए हैं। हर 500 मीटर पर जवान तैनात किए गए हैं। ओपी पर दो-दो तस्करों ने ड्रोन तैनात किए गए हैं। एक सप्ताह चलने वाले इस ऑपरेशन के दौरान गांवों सीमाएं भी सील रहेंगी। गांवों में नाके लगाए जाएंगे। हर गाड़ी को चेक किया जाएगा। होटलों की नियमित जांच होगी। बाहरी वाहन और लोगों पर विशेष नजर रहेगी। इस कड़ाके की टंड में जब जनता रजाइयों में दुबकी रहती है बीएसएफ के जवान बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। ड्रोन से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करों रोकना बीएसएफ के लिए चुनौती बनी हुई है। पिछले दिनों

मौटर तक नजर रखी जा रही है। सीमा पर पाक रेंजर्स की हरकत दिखाई देने पर कंट्रोल रूम से तत्काल कमांडेंट और अन्य अधिकारियों तक मैसेज जाता है। ड्रोन से होरोइन और हथियार तस्करों को रोकने के लिए व्हीकल माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके लिए दो तरह के वाहन तैयार किए गए हैं जिन पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। इन दोनों गाड़ियों पर करीब 10 जवान हथियारों से लैस होकर सीमा चौकी से 10

किलोमीटर तक के दायरे में 24 घंटे रेकी करेंगे। पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में 6 किलोमीटर तक उड़ान भरकर हथियार और मादक पदार्थ गिरा कर चले जाते हैं। बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट को देखते हुये बीएसएफ ने सीमावर्ती गांव में भी सर्विलांस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। ग्राम रक्षक समितियों को भी अलर्ट किया गया है। ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि संदिग्ध दिखाई देने वाले किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में तत्काल पुलिस थाना या बीएसएफ चौकी पर सूचना दें।

वहीं पति से भरण-पोषण की मांग करते हुये दायर परिवार में महिला ने कहा कि वह कोई काम नहीं जानती। वह पीहर पक्ष पर आश्रित है और पीहर पक्ष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पीहर पक्ष लंबे समय तक उसका भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह उन पर ज्यादा दिनों तक बोझ नहीं बने रहना चाहती है, इसलिए

लिव-इन में रहने वाली महिला को पति से गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, याचिका खारिज

जोधपुर, (कासं)। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली शादीशुदा महिला को उसके पति से गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। जोधपुर फैमिली कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुये ये फैसला सुना

शिक्षा संस्कृति एवं उत्थान के कार्य राष्ट्रीय हित में : पुरोहित

पोकरण, (निसं)। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के अवसर पर एक माह तक ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसके न्यास द्वारा ज्ञान महाकुंभ का पोस्टर विमोचन पोकरण नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, पंचायत समिति सांकड़ा प्रधान भगवत सिंह तंवर, शिक्षाविद अनिल शर्मा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित नारायणसिंह तंवर, राजपूत सेवा समिति पोकरण के अध्यक्ष एवं समाजसेवी बलवंत सिंह जोधा, न्यास के जैसलमेर प्रतिनिधि विक्रम सिंह रावलोत, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के संभागीय संगठन मंत्री राणीदान सिंह भुट्टो ने गुरुवार को पंचायत समिति सांकड़ा सभागार में किया गया।

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के विक्रम सिंह ने न्यास का परिचय देते हुए बताया कि प्रयागराज में ज्ञान महाकुंभ परिसर में प्राथमिक शाला के शिक्षक से लेकर उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा प्रबंधन शिक्षा के बड़े-बड़े संस्थाओं के निदेशक, कुलपति, कुलाधिपति, शिक्षा मंत्री, अभिभावक और विद्यार्थी सभी मिलकर देश के वर्तमान एवं भविष्य के शैक्षिक परिदृश्य

पर विचार मंथन करेंगे। उन्होंने बताया कि ज्ञान महाकुंभ का शुभारंभ 10 जनवरी 2025 को हो गया है। जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है। नारायण सिंह तंवर ने बताया कि देशभर में शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सार्थक कार्यों को एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। साथ ही प्रतिदिन शिक्षा के अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही पर्यावरण के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का समाधान करने में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय जीवन शैली की भूमिका को लेकर 31 जनवरी को इसी कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय हरित महाकुंभ का आयोजन होगा। जिसमें देश भर के पर्यावरणविद एक साथ जुड़ेंगे और जल, जमीन, जंगल, नदी व ग्लोबल वार्मिंग सहित पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन कर पर्यावरण घोषणा पत्र जारी करेंगे।

राणीदान सिंह भुट्टो ने बताया कि ज्ञान महाकुंभ में 7, 8 और 9 फरवरी को राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिसकी थीम भारतीय ज्ञान परंपरा एवं शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत रहेगी। 7 फरवरी को शिक्षा क्षेत्र

■ पोकरण में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर ज्ञान महाकुंभ का पोस्टर विमोचन किया गया

में कार्य कर रहे पूज्य संतों, गुरुकुल संचालकों, निजी क्षेत्र में सेवा भाव से कार्य करने वाले शैक्षिक संस्थानों का सम्मेलन होगा। अगले दिन 8 फरवरी को शिक्षा क्षेत्र में शासन प्रशासन की भूमिका को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिसमें देशभर के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, अखिल भारतीय शैक्षिक संस्थानों के निदेशक, चेयर पर्सन, कुलपति कुलाधिपति, शैक्षिक संस्थानों के संचालक, संस्था प्रधान इत्यादि सम्मिलित होंगे जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन एवं भारत केंद्रित शिक्षा पर विशेष चिंतन मनन संवाद होगा तथा राष्ट्रीय शिक्षा शैक्षिक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। विमोचन के अवसर पर

नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा किया गया किया जा रहा कार्य राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक एवं उपयोगी सिद्ध होगा है।

पंचायत समिति प्रधान भगवत सिंह तंवर ने विमोचन के अवसर पर कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा एवं कौशल के आधार पर भावि राष्ट्र के करणधारों के निर्माण में इस ज्ञान महाकुंभ में लिए जाने वाले निर्णय इंडिया से भारत की ओर ले जाने का मोल का पत्थर साबित होगा। शिक्षाविद अनिल शर्मा ने बताया कि ज्ञान महाकुंभ के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा एवं शिक्षा पद्धति को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को भाग लेना का आह्वान किया। इसके बाद न्यास के प्रतिनिधियों ने पोकरण प्रवास पर आये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर शंकर सिंह उदावत, जैसलमेर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेशदत्त, पोकरण ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेमशंकर जोशी पोकरण शहर यू सी ओ गोविंद कुमार से भेंटकर उन्हें ज्ञान महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया।

पथ संचलन निकाला 'अपात्र लोगों से होगी वसूली'

रेवदर, (निसं)। रेवदर कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक रेवदर में सुभाष चंद्र बोस जयंती के निमित्त प्रधानाचार्य प्रवीण रावल व शिक्षकों के नेतृत्व में विद्या मंदिर के भैया बहिनों द्वारा नगर के मुख्य मार्ग से विशाल पथ संचलन निकाला गया।

नगर में पथ संचलन के समय नगर निवासियों ने भैया-बहिनों का पुष्प वर्षा कर स्वागत व उत्साह वर्धन किया। पथ संचलन आदर्श विद्या मंदिर कार्यालय, राणा चौक, बस स्टैंड, तहसील चौराहा, सेलवाडा रोड, रामदेव गली होते हुए पुनः विद्या मंदिर पहुंचा।

पथ संचलन के पश्चात सामूहिक कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण रावल द्वारा सुभाष चंद्र बोस के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमेशा ध्यान रहा है, कि वह राष्ट्रीय एकता को बल देते थे और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए ताकतवर व बलशाली राष्ट्र

की कामना करते थे। हमें नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर बलशाली राष्ट्र की कामना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी।

उन्होंने भारतवासियों के दिलों में देशभक्ति की ऐसी अलख जगाई, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनका नारा 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' आज भी हर भारतवासी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस मौके पर विद्यालय के आचार्य तेजाराम ने सुभाषजी की जीवनी पर बातचीत की तथा कहा कि उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी सबके प्रेरणा स्रोत बनें। नेताजी के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि भारत माता के महान सपूत और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन साहस, निष्ठा और निस्वार्थ सेवा की मिसाल है। इस अवसर पर विद्या मंदिर के भैया-बहिन सहित सभी आचार्य-आचार्याओं की उपस्थिति रही।

जैसलमेर, (नि.सं.)। जिले में खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूँ लेने वाले अपात्र लोगों की जल्द ही पोल खुलने वाली है। इसके लिए रसद विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग का गिवअप अभियान अभी जारी है। अपात्र लोग अभी स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं, इसके बाद विभाग की ओर से उनसे वसूली की जाएगी। यह अभियान विभाग की ओर से 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। जिले में अब तक रसद विभाग की गिवअप योजना से सक्षम व्यक्तियों में जागरूकता आई है। अब तक जिले में स्वेच्छा 329 कार्ड धारकों ने गिव-अप अभियान में अपनी पात्रता छोड़ चुके हैं।

जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में इसके बाद विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा से जुड़े उपभोक्ताओं की जांच की जाएगी। यह सभी जांच ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसमें उपभोक्ताओं के बैंक खाते और

परिवहन विभाग आदि से जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें योजना के तहत अपात्र पाए जाने वाले उपभोक्ताओं से 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। इससे उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान में आयकरदाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकार कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्त संस्था में कर्मचारी/अधिकारी एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय व परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जोविकोपार्जन में प्रयोग आते हैं को छोड़कर निष्कासन सूची में सम्मिलित है। इसके लिए राषन की दुकानों पर गिव-अप फार्म भरे जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति निकटवर्ती राषन की दुकान पर गिव-अप अभियान का फार्म भरकर राषन की दुकान पर ही जमा करा सकते हैं।



LIC
एलआईसी

**एलआईसी के साथ
अपना विकास सुनिश्चित करें**

- तीन साल के लिए स्टाइपेंडरी स्कीम।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास से लेकर कोई भी उच्च शिक्षा।
- न्यूनतम पूर्ण आयु: आवेदन के समय 18 वर्ष।
- एजेंसी स्टाइपेंडरी अवधि में एवं उसके पश्चात नियमानुसार कमीशन के साथ जारी रहेगी।
- शर्तों के अधीन एलआईसी अपने एजेंट्स को कैरियर के अवसर भी प्रदान करती है।
- निर्दिष्ट मानदंडों की प्राप्ति पर आधारित स्टाइपेंडरी योजना

स्वावलंबी नारी, खुशहाली हमारी

आवेदन के लिए, नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या www.licindia.in पर विज़िट करें

हमें फॉलो करें:  LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

ग्राम फोन कॉल और झूठे/घोषाघड़ी वाले ऑफर्स से सावधान रहें, आईआईसीआई बीमा पॉलिसी बेचने या बीमस की घोषणा करने या प्रीमियम के निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता, जनता से निवेदन है कि ऐसे फोन कॉल करने पर वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, जोखिम घटकों, नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया किसी से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

**ईश्वर का है अनमोल उपहार
बेटी को मत समझो भार**

राष्ट्रीय बालिका दिवस

24 जनवरी, 2025

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत
गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है



श्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री राजस्थान

वैधानिक चेतावनी

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 (PCPNDT) के तहत गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण/चयन करना अथवा करवाना, इसके लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। इस कृत्य के लिए 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

**मुखबिर योजना के तहत
3 लाख रुपये तक का इनाम**

भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना पर

आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है तो टोल फ्री नं. **104/108** या वाट्सएप नं. **9799997795** पर शिकायत दर्ज कराएं, मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर

डोटासरा झूठ का ढोल है, जिसे कोई भी बजा जाता है : सुरेश सिंह रावत

जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि कांग्रेस को राम के नाम से ही खिड़ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य नदी जोड़ो परियोजना में राजस्थान के शब्द से "रा" और मध्य प्रदेश के शब्द से "म" लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की 40 प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

रावत ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा एक झूठ का ढोल है और उसे कोई भी बजा जाता

प्रदेश की जनता पहले ही कांग्रेसियों को आईना दिखा चुकी है

है। डोटासरा ऐसे झूठ के ढोल से अपनी भद पिटा रहे हैं। उनको अपने गिरेबां में झांकना चाहिए कि पिछले कार्यकाल में उनकी अतिवादी मानसिकता की वजह से आज कांग्रेस को दुर्दशा हुई है और उपचुनाव में भी जनता ने करारी चोट दी है। मंत्री ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों को वर्ष 2054 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध

होगा। इस परियोजना में 522 एमसीएम पुनर्चक्रित जल सहित कुल 4.102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि एमओए होने से कालीसिंह का 50 प्रतिशत निर्भरता पर जल मिलेगा। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा साफ है कि पूर्वी राजस्थान को पेयजल एवं सिंचाई समस्या दूर हो।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिन-रात राजस्थान के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। यह कांग्रेसियों को हजम नहीं

हो रहा है। क्योंकि होटलों से सरकार चलाने वाले ये लोग कभी जनता की भावना को समझ ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसम्बर 2024 को परियोजना के 10 हजार करोड़ कार्यों का शिलान्यास किया है। अतः कांग्रेसी झूठ को राजनीति से बाहर आए और जनता के हित में काम करें।

विगत कांग्रेस सरकार द्वारा ईआरसीपी को कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया गया था ना ही कोई नये कार्य प्रारम्भ किये गये। प्रधानमंत्री के प्रयासों से इस परियोजना को मूर्त रूप दिया गया है।

जयपुर में एच.एम.पी. वायरस के दो मरीज मिले

जयपुर। राजधानी जयपुर में कोविड जैसे ही एच.एम.पी. वायरस के दो पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती एक महिला और एक पुरुष को जांच में इस वायरस की पुष्टि हुई है।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर भारती मल्होत्रा ने बताया कि अस्पताल में 2 दिन पहले सैपल जांच के लिए आए थे। इनमें एच.एम.पी. वायरस की पुष्टि हुई है। डॉक्टर भारती मल्होत्रा ने बताया कि सवाई मानसिंह अस्पताल में इस साल के पहले दो केस हैं। अस्पताल में भर्ती यह दोनों मरीज सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। इसके अलावा अन्य दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित होने के कारण पिछले दिनों एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। डॉ.

मल्होत्रा ने बताया कि इस केस के मामलों की जांच हम पिछले 12-15 साल से करते आ रहे हैं। इस वायरस की अक्टूबर से लेकर मार्च तक प्रभाव ज्यादा रहता है। साल 2024 में अक्टूबर-नवंबर में इस वायरस के 2-2 केस आए थे। इसी तरह शुरुआती सीजन सानी जनवरी, फरवरी और मार्च में 13, 34 और 20 केस डिटैक्ट हुए थे। कुल 71 केस डिटैक्ट हुए थे। इसी तरह साल 2023 में भी इसके 23 से ज्यादा केस जयपुर में डिटैक्ट हुए थे। डॉ. मल्होत्रा ने बताया कि साल 2012-13 में एक स्टडी की गई थी, जिसमें जयपुर समेत आसपास के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती ऐसे छोटे बच्चे (5 साल तक के) जिनमें सीवियर एक्ज्यूट रिसप्टरी ईंफेक्शन से जुड़ी समस्या थी।

सार-समाचार सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन



जयपुर। भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन की और से आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह जगतपुर स्थित पूर्णिमा युनिवर्सिटी, जयपुर में संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रानु शर्मा ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जागरूकता ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धुवनेश जैन ने युवाओं को सड़क सुरक्षा के महत्व और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, युवाओं में सही आदर्श और जिम्मेदारी की भावना ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकती है। उन्होंने बताया सप्ताह के दौरान, जयपुर शहर में विभिन्न रैलियों, वर्कशॉप्स और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में हजारों युवाओं ने भाग लेकर शहर के प्रमुख स्थलों पर यातायात को नियंत्रित करने और नागरिकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने में सहायता की। कार्यक्रम का समापन प्रोफेसर मोनिका खत्री, विभागाध्यक्ष, बीबीए/विभाग, डॉ. मनोज गुप्ता, प्रो-उपकुलपति और डॉ. चान्दनी कुपलानी, प्रो-उपकुलपति, द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने सभी प्रतिभागियों और आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया और सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी को प्रेरित किया।

साइबर एक्सपर्ट की मदद से चार दिन बाद खुला विवाहिता की मौत का राज

जयपुर। शहर के नामी स्कूल की टीचर के सुसुराल में सीडियों से पैर फिसलकर गिरने से मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मौत के 4 दिन बाद साइबर एक्सपर्ट से मोबाइल लोक खलवाने पर खुद के सुसाइड का पता चला। सुसाइड से 14 घंटे पहले टीचर ने रोते हुए चार वीडियो अपने मोबाइल में बनाए थे। श्याम नगर थाने में मृतका के पिता ने पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है।

पुलिस ने बताया कि राती सती नगर निर्माण नगर निवासी सुरेंद्र कुमार जैन ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि बेटी मुस्कान जैन (26) की दहेज हत्या के लिए प्रियांशु शर्मा, ससुर निर्मल शर्मा व सास मितु शर्मा जिम्मेदार हैं। गत 9 नवम्बर-2022 को निर्माण नगर श्याम नगर निवासी प्रियांशु शर्मा से मुस्कान की शादी हुई थी। जनवरी-2023 में मुस्कान व प्रियांशु चंडीगढ़ में रहने लगे थे। तभी से दोनों में दहेज को लेकर अनबन शुरू हो गई। परेशान होकर 6 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2023 तक मुस्कान पीहर में रही। घर नहीं टूटे इसलिए पति प्रियांशु के कहने पर वापस ससुराल चली गई। जनवरी-2024 को मानसरोवर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में साइस पढ़ाने लगीं। गत 5 जनवरी को सुबह ससुरालवालों ने गोपालपुरा

बाइपास स्थित भण्डारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेडिकल सूचना पर आई पुलिस को बताया गया कि मुस्कान घर में दूसरी मंजिल की सीडियों से फिसल गिर गई थी। हॉस्पिटल में 7 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद 12 जनवरी को रात मुस्कान की मौत हो गई।

पिता सुरेंद्र कुमार जैन ने बेटी मुस्कान की मौत के बाद उसके मोबाइल का लोक एक्सपर्ट से खलवाने को दिया। मौत के चार दिन बाद एक्सपर्ट ने मोबाइल लोक खोलकर उन्हें दिया। मोबाइल चौक करने पर मुस्कान के सीडियों से फिसलने से मौत नहीं होकर सुसाइड करने का पता चला। घर के आंगन में ही दूसरी मंजिल से मुस्कान ने छलांग लगाई थी। सुसाइड से करीब 14 घंटे पहले उसने अपने मोबाइल में चार वीडियो बनाए थे। गत 4 जनवरी को शाम मुस्कान ने पहला वीडियो बनाया था। मोबाइल में मिले चार वीडियो 23.14 मिनट, 1.23 मिनट, 45 सेकंड और 2 सेकंड का है। उसमें मुस्कान रोते हुए पति प्रियांशु शर्मा, सास मितु शर्मा और ससुर निर्मल शर्मा की ओर से की गई प्रताड़ना को बता रही है। आत्महत्या के लिए भी इन तीनों को ही जिम्मेदार बताया है। मृतका के पिता ने श्याम नगर थाने में पति व सास-ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है।

कृषि उपज मंडियों में 7 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 23 लाख से अधिक की लागत के नवीन कार्यों को मंजूरी दी है। इनमें कृषि उपज मंडी समिति पीलीबंगा (हनुमानगढ़) के उप मंडी यार्ड जाखड़ावाली में नवीन निर्माण कार्यों हेतु 3 करोड़ 53 लाख रुपये, कृषि उपज मंडी जोधपुर (फ.स.) में नवीन सब्जी मंडी प्रांगण भववासिया में पुरानी सीवर लाइन परिवर्तन एवं कार्यालय भवन के विस्तार हेतु 2 करोड़ 16 लाख रुपये एवं विद्युत संबंधी कार्यों के लिए 1.1 लाख 85 हजार रूपए की मंजूरी दी है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने कृषि विपणन अधिकारी कोटे के चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली के नियुक्ति वारंट जारी किए



प्रमिल कुमार माथुर



चंद्र प्रकाश श्रीमाली



चंद्र शेखर शर्मा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेजी सिफारिश को मंजूर करते हुए राष्ट्रपति की ओर से न्यायिक अधिकारी कोटे के चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली के नियुक्ति वारंट जारी किए

हैं। तीनों न्यायाधीशों को जल्दी ही हाईकोर्ट जज के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। प्रमिल कुमार माथुर वर्तमान में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं। वहीं चंद्र प्रकाश श्रीमाली जयपुर महानगर द्वितीय के जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश हैं। जबकि

चंद्रशेखर शर्मा जोधपुर में डीजे पद पर कार्यरत हैं। इनके शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगी। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों को कुल 50 पद स्वीकृत हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में आज तक कभी भी पूरे 50 पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं।

'विश्व में लगातार बढ़ रही है भारत की प्रतिष्ठा'

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा द्वारा की जा रही बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं,

भारत की अर्थव्यवस्था में भी लगातार सुधार हो रहा है और भारत में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं का भी लगातार क्रियान्वयन किया जा रहा है। विश्व के 45 से अधिक देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बावजूद कांग्रेसी नेताओं को यह नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में गहलोत और इनके नेताओं को अपना चरम बदलना चाहिए। गहलोत अभी अपनी ओड़ी

राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए। वहीं डोटासरा जी तो लगातार बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो क्या कहते हैं।

पुनर्ग्रहण शुल्क लेकर भूखंडों की निर्माण अवधि बढ़ायेगी सरकार

नगरीय विकास विभाग ने आमजन के हित में जारी किए आदेश

जयपुर। नगरीय विकास विभाग अब पुनर्ग्रहण शुल्क लेकर आमजन को सरकारी योजनाओं में आवंटित भूखंडों पर निर्माण करने की अवधि में छूट देगा। राज्य सरकार ने जनहित में यह कदम उठाया है। नगरीय विकास विभाग के इस आदेश के बाद हजारों ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा, जिन्होंने विकास प्राधिकरण और नगरीय निकायों में सरकारी भूखंड तो आवंटित करवा लिए, लेकिन उन पर तय समय में निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सके।

जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि

इस आदेश के बाद हजारों ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा, जिन्होंने विकास प्राधिकरण और नगरीय निकायों में सरकारी भूखंड तो आवंटित करवा लिए, लेकिन उन पर तय समय में निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सके।

निष्पादन) नियम 1974 के नियमों के तहत भवन निर्माण के लिए समयावधि का निर्धारण किया गया है, इस अवधि में निर्माण नहीं करवाये जाने पर भूखंडों का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण शुल्क लिया जाकर भूखंडों की बहाली

ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों को ब्याज और पेनल्टी में छूट

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने नगरीय विकास विभाग के आदेशों की अनुपालना में ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों से प्रथम किश्त 31 मार्च 2025 तक जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी में छूट दी है।

जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी ने बताया कि नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटियों को चार त्रैमासिक किस्तों में ब्याज-पेनल्टी में छूट के साथ राशि जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह छूट प्रथम किश्त 31 मार्च 2025 तक जमा करवाने की शर्त पर दी गई है। उल्लेखनीय है कि जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों द्वारा आवंटन पत्र जारी करने एवं बिना ब्याज व शांति की राशि जमा करने के लिए बार-बार जेडीसी से निवेदन किया गया।

गेमिंग जॉन में अग्निशमन इंतजाम जांचने पहुंची ग्रेटर निगम की टीम

जयपुर। ग्रेटर निगम आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देश पर गुरुवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमलाल और उनकी टीम ने शहर में गेमिंग जॉन का औचक निरीक्षण किया। टीम ने सभी जगहों पर अग्निशमन व्यवस्था देगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमलाल ने बताया कि लेट्स गेमिंग जॉन इस्कान रोड मानसरोवर में संचालित प्ले जॉन, पानबर्ग गेमिंग जॉन पत्रकार कॉलोनी रोड मानसरोवर, जॉिंग नेशन गेमिंग जॉन कृष्णा सरोवर मानसरोवर में संचालित प्ले जॉन में वर्तमान में अग्निशमन उपकरण कार्यशील अवस्था में पाए गए।

राजस्थान-उत्तरप्रदेश में छापेमारी के दौरान आरोपी संजय शर्मा, बच्चों की विदेशी शिक्षा के दस्तावेज, कई भूखंड व मकान, दो बैंक लॉकर्स और खाते तथा कई बीमा पॉलिसियों में निवेश मिला है

जयपुर। ग्रेटर निगम आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देश पर गुरुवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमलाल और उनकी टीम ने शहर में गेमिंग जॉन का औचक निरीक्षण किया। टीम ने सभी जगहों पर अग्निशमन व्यवस्था देगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमलाल ने बताया कि लेट्स गेमिंग जॉन इस्कान रोड मानसरोवर में संचालित प्ले जॉन, पानबर्ग गेमिंग जॉन पत्रकार कॉलोनी रोड मानसरोवर, जॉिंग नेशन गेमिंग जॉन कृष्णा सरोवर मानसरोवर में संचालित प्ले जॉन में वर्तमान में अग्निशमन उपकरण कार्यशील अवस्था में पाए गए।

राजस्थान-उत्तरप्रदेश में छापेमारी के दौरान आरोपी संजय शर्मा, बच्चों की विदेशी शिक्षा के दस्तावेज, कई भूखंड व मकान, दो बैंक लॉकर्स और खाते तथा कई बीमा पॉलिसियों में निवेश मिला है

जयपुर। ग्रेटर निगम आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देश पर गुरुवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमलाल और उनकी टीम ने शहर में गेमिंग जॉन का औचक निरीक्षण किया। टीम ने सभी जगहों पर अग्निशमन व्यवस्था देगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमलाल ने बताया कि लेट्स गेमिंग जॉन इस्कान रोड मानसरोवर में संचालित प्ले जॉन, पानबर्ग गेमिंग जॉन पत्रकार कॉलोनी रोड मानसरोवर, जॉिंग नेशन गेमिंग जॉन कृष्णा सरोवर मानसरोवर में संचालित प्ले जॉन में वर्तमान में अग्निशमन उपकरण कार्यशील अवस्था में पाए गए।

वरिष्ठ ट्रांसपोर्ट अधिकारी के 10 से ज्यादा ठिकानों पर ए.सी.बी. की छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति मिली

राजस्थान-उत्तरप्रदेश में छापेमारी के दौरान आरोपी संजय शर्मा, बच्चों की विदेशी शिक्षा के दस्तावेज, कई भूखंड व मकान, दो बैंक लॉकर्स और खाते तथा कई बीमा पॉलिसियों में निवेश मिला है

जयपुर। प्रशासन निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने राजधानी जयपुर में तैनात वरिष्ठ ट्रांसपोर्ट अधिकारी संजय शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की है। ए.सी.बी. टीम ने राजस्थान के अलग-अलग शहरों के साथ उत्तर प्रदेश के भी एक शहर में छापेमारी की है। गुरुवार सुबह 7 बजे से चली इस कार्रवाई में 5 से ज्यादा ठिकाने शामिल थीं। एजेंसी के पास अधिकारी के खिलाफ प्रशासन को लेकर काफी शिकायतें पहुंची थीं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसबी अजमेर भागदंड मीणा ने बताया कि एआरटीओ संजय शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर कार्रवाई की जा रही है। विद्याधर नगर परिवहन कार्यालय में पोस्टेड शर्मा के खिलाफ कोर्ट से परमिशन ली गई थी। उनके जयपुर, भरतपुर, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ए.सी.बी. की एक टीम जयपुर के एक एफ.के.जे. ज्वैलर्स के यहां भी पहुंची है। मीणा ने बताया कि आरोपी अधिकारी के मुरादाबाद के पैतृक गांव में भी सर्च किया, यहां



आरोपी संजय शर्मा

उनके रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं जयपुर में वैशाली नगर, श्याम नगर, पांच्यावाला में आरोपी अधिकारी से जुड़े दोस्तों व अन्य लोगों के यहां भी टीम पहुंची है। जानकारी के अनुसार जयपुर में कुल 8 जगह एजेंसी जांच कर रही है। एफआईआर में जिन

संजय शर्मा जयपुर के विद्याधर नगर में वरिष्ठ ट्रांसपोर्ट अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। गुरुवार सुबह 7 बजे अचानक ए.सी.बी. की टीम ने इनके राजस्थान और उत्तरप्रदेश के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया।

बताया जा रहा है कि ए.सी.बी. को शिकायत मिली थी कि संजय शर्मा ने अवैध पैसे से गोल्ड भी खरीदा है। यह सोना एस.के.जे. ज्वैलर्स से खरीदा गया है, इस पर ए.सी.बी. की एक टीम ज्वैलर के वैशाली नगर स्थित शोरूम में भी पहुंची।

दस्तावेजों की जानकारी दी गई है। उनके मिलने पर उसे वॉरेंट वीरफाई किया जायेगा। बैंक खातों के नंबर भी प्राप्त किए जा रहे हैं। इनकी पत्नी और बच्चों के नाम से 4-5 बैंक खाते मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है। जमीनों के दस्तावेजों के जानकारी भी मिली है। पत्नी के नाम से जमीन ली हुई है। एसबी से मिली जानकारी के अनुसार संजय शर्मा ने अवैध पैसे से गोल्ड भी खरीदा है। यह सोना संजय शर्मा के ने एस.के.जे.

आवास, पांच्यावाला में अधिकारी के पत्नी के नाम प्लॉट पर, बिलारी मुरादाबाद में अधिकारी के चचेरे भाई के घर, विद्याधर नगर में अधिकारी के रिश्तेदार के घर और लक्ष्मी कॉलोनी सांगर में अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार के घर पर तलाशी ली गई।

ए.सी.बी. महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि आरोपी संजय शर्मा और उसके परिवारजनों के नाम पर कृष्णा नगर में एक मकान, कर्पाणी नगर में एक प्लॉट, अलीगढ़ उत्तरप्रदेश में एक भूखंड, चिड़िया भवन, बिलालारी मुरादाबाद (यूपी) में 25 बीघा जमीन मिली है। संजय शर्मा द्वारा अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए विदेश में करवाने संबंधी दस्तावेज, कई बीमा पॉलिसियां, दो बैंक लॉकर और कई बैंक खाते मिले हैं, जिनमें लाखों र. जमा है। फिलहाल बैंक लॉकर और खातों को खोला जाना शेष है। एसबी को शक है कि संजय शर्मा ने कई जगहों पर बेनामी संपत्तियों में भी निवेश कर रखा है, इसे लेकर भी जांच की जा रही है।

लूट व हत्या के मामले में पकड़े गए बदमाशों की परेड निकाली

जयपुर। विद्याधर नगर थाना इलाके में महिला से लूट और हत्या के मामले में पकड़े गए पांचों बदमाशों की गुरुवार को पुलिस ने परेड निकाली। इस दौरान बदमाश फ्रेंचवर्क हुए पैर से लंगड़ाते हुए चलते रहे। थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि गुरुवार को पांचों बदमाशों की परेड कराई गई। टूटे पैर पर प्लास्टर चढ़े दोनों हत्या के आरोपी लंगड़ाते हुए वारदात स्थल तक पहुंचे। पुलिससिक्तियों ने सहारा देकर आरोपी लक्की और शाहरुख को रोड पर घुमाया। उनके पीछे-पीछे तीनों मास्टरपाइंड को लेकर पुलिस टीम भी पहुंची। पांचों बदमाशों से पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तस्वीर की कार्रवाई पूरी कराई। गौरतलब है कि 16 जनवरी को विद्याधर नगर में महिला सरोज बंसल (55) की लूट के लिए हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के लिए महिला की हत्या मामले में मास्टरपाइंड गोपाल शर्मा (45), बजरंग लाल (50), दीन मोहम्मद चढ़े दोनों हत्या के आरोपी लंगड़ाते हुए वारदात स्थल तक पहुंचे। पुलिससिक्तियों ने सहारा देकर आरोपी लक्की और शाहरुख को रोड पर घुमाया। उनके पीछे-पीछे तीनों मास्टरपाइंड को लेकर पुलिस टीम भी पहुंची। पांचों बदमाशों एक पैर फ्रेंचवर्क हो गए थे।

सड़कों पर गड्डों से हादसे, लोगों में आक्रोश पनपा

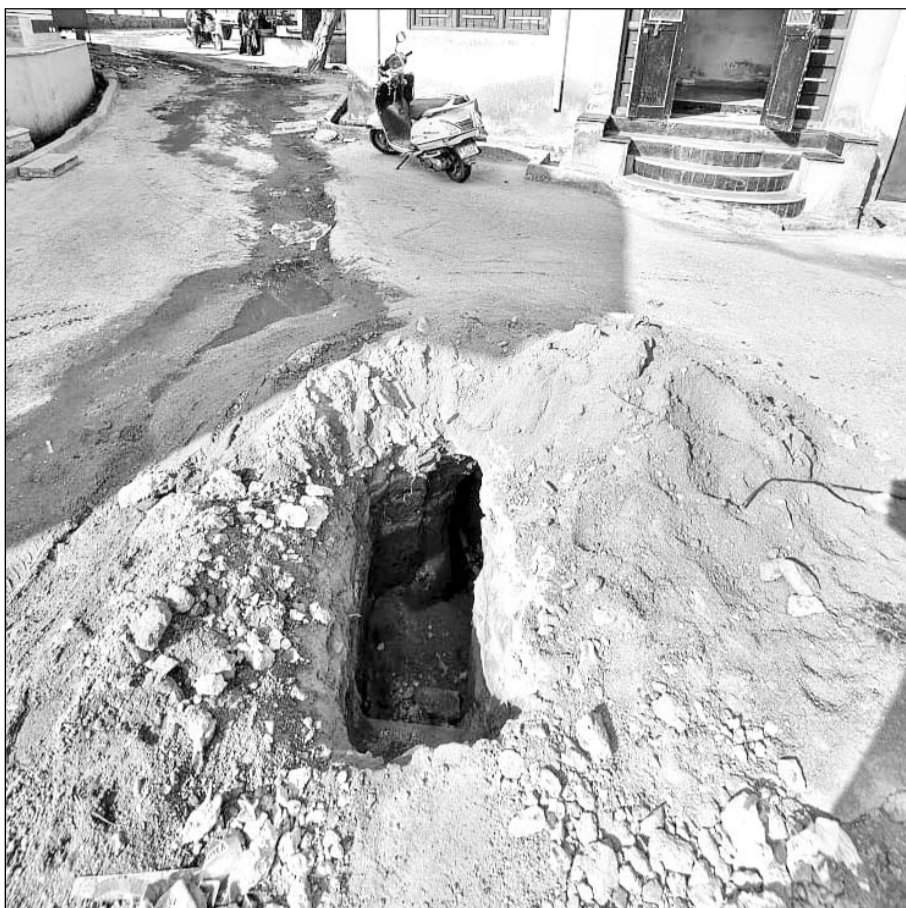
जालोर, (कासं)। जालोर शहर के लाल पोल के अन्दर श्रेष्ठ निवास के सामने एक निजी गैस कंपनी द्वारा गड्ढे खोद कर छोड़ देने से लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि प्रत्येक सड़क को दो से तीन बार खोदा गया है जिससे सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।

जालोर शहर के विभिन्न मोहल्लों में लोगों के घरों में गैस लाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढे आमजन के लिए परेशान का कारण बन गए हैं। सड़कों पर दोनों तरफ इन गड्ढों में आए दिन वाहन फंस रहे हैं, जिससे वाहन चालक चोटिल भी हो रहे हैं।

लालपोल के अंदर शिवबाड़ी के पास से गुजर रहा एक पिकअप टोला भी गड्ढे में धंस गया, वाहन चालक के काफी प्रयास के बावजूद नहीं निकला तो आसपास की महिलाओं व लोगों की सहायता से बड़ी मुश्किल से वाहन बाहर निकाला जा सका। गैस लाइन कार्य के दौरान गैस लाइन वालों ने एक बड़ा गड्ढा खोदकर रख दिया यह गड्ढा एक सप्ताह से खुदा हुआ पड़ा है इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है इस गड्ढे के कारण आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है अगर इसे बंद नहीं किया तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। खुले गड्ढे से हादसे का खतरा बढ़ सकता है।

लोगों का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि वे इसे जल्द से जल्द ठीक करें और सुरक्षा के उपायों को सुनिश्चित करें। साथ ही बताया कि गैस लाइन की मरम्मत के लिए जिम्मेदार विभाग को भी चाहिए कि वे समय पर काम खत्म करें और आसपास के लोगों को इस खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए उचित कदम उठाए।

पुर्व पार्षद अयूब शेख ने बताया



जालोर में लाल पोल के अन्दर श्रेष्ठ निवास के सामने खुला खड्डा हादसे को न्यौता दे रहा है। फोटो-राष्ट्रदूत

कि पिछले कई दिनों से गैस लाईन डालने को लेकर मोहल्ले की सड़क के किनारे बड़े बड़े खड्डे खोद कर छोड़ देते हैं।

रात्रि के समय पैदल चलने चलने वाले राहगीर शिकार हो रहे हैं। मोहल्लेवासी मोहम्मद आरीफ ने

बताया कि मेरे घर के आगे बड़ा खड्डा खोद कर छोड़ दिया है, जिससे एक बुरा गिर गया। जिससे उसके हल्की चोट आई है वही इस सड़क पर सुबह बच्चे विद्यालय जाते हैं।

पार्षद सुशीला मेघवाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से लाल पोल के

अन्दर एक निजी कंपनी द्वारा बार बार सड़कों को क्षतिग्रस्त किया जा रही है जिससे आमजन को परेशान हो रही है। इस समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं सुभाषचंद्र बोस : चौहान



धोरीमन्ना में आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ने पथ संचलन निकाला।

फोटो-राष्ट्रदूत

धोरीमन्ना, (कासं)। विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक धोरीमन्ना की ओर से गुरुवार को धोरीमन्ना के विभिन्न मार्गों पर बोस जयंती पर पथ संचलन निकाला गया।

संचलन विद्यालय प्रांगण से रवाना होकर गायत्री मंदिर, आलम जी मंदिर परिसर, सुभाषनगर, मुख्य चौराहा, नया बाजार व मुख्य बाजार से होते हुए विद्यालय पहुंचा। विद्यालय के निदेशक तेज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में

बताया कि सुभाषचंद्र बोस सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। इनके पद चिन्हों पर चलते हुए युवा अपने राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर कार्य करें। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला महाविद्यालय विद्यार्थी सह प्रमुख राजुराम कडवासय ने अपने आशीर्वाचन में बताया कि बोस की जयंती पर हम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर देश और धर्म के लिए हर समय कंधे से कंधा मिलाकर तत्पर रहें। नगर वासियों द्वारा गर्म जोशी

के साथ संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। छोटे भैया बहनों द्वारा मुख्य चौराहों पर झांकी प्रदर्शन किया गया।

समिति के कोषाध्यक्ष राजेंद्र मालू, अध्यक्ष सुरेश कुमार गुलार, उपाध्यक्ष भीमराज सोनी, समिति सदस्य व पूर्व भैया उपस्थित रहे। संचलन में 315 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता निभाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य नारायण दास माली ने आभार व्यक्त किया।

अहिल्या बाई की संकल्प शक्ति ने समाज को नई ऊंचाईयां दी : शेखावत

जोधपुर, (नि.सं.)। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय स्थित बृहस्पति सभागार में आज अहिल्या बाई होल्कर त्रिशताब्दी जयंती समारोह का आयोजन किया गया।

विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग, राजनीति विज्ञान विभाग, महिला अध्ययन केंद्र और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि अहिल्या बाई होल्कर ने विभिन्न कठों के बाद भी अपनी संकल्प शक्ति से समाज को नई ऊंचाईयां दी। उन्होंने मुगलकाल में हुए विध्वंस का पुनर्निर्माण कर धन का सदुपयोग किया। शेखावत ने कहा कि जो समाज इतिहास से प्रेरणा नहीं लेता वह अपनी जड़ों से कट जाता है। इस दौरान शेखावत ने कुंभ मेले का सांस्कृतिक महत्व बताते हुए कहा कि यह समझना के साथ धारण को समझना है तो कुछ दिन कुंभ में रहे। कुंभ भारत के विराट रूप का दर्शन है।

समारोह के मुख्य वक्ता और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन मंत्री डॉ. बालमुकुंद पाण्डेय ने कहा कि अहिल्या बाई होल्कर सामाजिक समरसता का उज्ज्वल



केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बृहस्पति सभागार में अहिल्या बाई होल्कर त्रिशताब्दी जयंती समारोह को संबोधित किया।

उदाहरण है। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, कुटुंब प्रबंधन, नागरिक बोध, महिला सशक्तीकरण, कर्तव्य पालन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया।

समारोह के सह वक्ता और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रो. शिव कुमार मिश्रा ने विस्तार पूर्वक विषय की प्रस्तावना पेश की। समारोह की अध्यक्षता करते हुए विवि कुलपति प्रो. केएल श्रीवास्तव ने अहिल्या बाई होल्कर के आदर्शों से प्रेरणा लेने की

बात कही। विशिष्ट अतिथि और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की अध्यक्षता प्रो. सुशीला शकतावत ने अहिल्या बाई का जीवन परिचय देते हुए मल्हारार और अहिल्या बाई के बीच हुए पत्र व्यवहार पर भी चर्चा की।

समारोह के समन्वय डॉ. भगवान सिंह शेखावत ने स्वागत उद्बोधन, डॉ. दिनेश राठी ने मंच संचालन और डॉ. विजयश्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

समारोह के दौरान बुधवार को विश्वविद्यालय में अहिल्या बाई होल्कर पर हुई प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

महानगर कार्यवाह मनोहर सिंह, पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत, प्रो एस पी व्यास, प्रो एफ के कपिल, प्रो ज्ञान सिंह, प्रो कर्मांत माधुर, प्रो राम सिंह प्रो कुलदीप मोणा, प्रो हीरामण, राजेंद्र सिंह ललित्या, शिवमंगल सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे।

कचरे में आग लगाते झुलसा 10 साल का बच्चा

पाली, (नि.सं.)। पाली शहर में खेलते समय एक 10 साल का बच्चा आग से बुरी तरह झुलसा गया। इलाज के लिए उसे पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। हादसे में मासूम के सीने, पेट का काफी हिस्सा जल गया। जिसका उपचार जारी है।

पाली शहर के निकट स्थित गुंदोज गांव में बुधवार शाम 5.30 बजे सुरेंद्र (10) अपने बड़े भाई देवेंद्र (11) पुत्र हरिराम के साथ घर में कागज का कचरा इकट्ठा कर उसे माचिस से आग लगा रहे थे। इस दौरान अचानक आग की लपटें निकट बैठे सुरेंद्र के शर्ट तक पहुंच गईं। जिससे वह जलने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर घर में झाड़ू लगा रही उसकी मां मनीषा और दादी डाखू देवी दौड़कर मौके पर गए और आग बुझाकर इलाज के लिए देर रात को पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की देखरेख में उपचार शुरू किया गया। झुलसे सुरेंद्र के पिता हरिराम ने बताया कि घटना के वक्त पत्नी और मां काम-काज में व्यस्त थीं। उन्होंने समझा कि दोनों भाई खेल रहे हैं। लेकिन माचिस की तीली से कागज के कचरे में आग लगाने के दौरान आग सुरेंद्र के कपड़ों तक पहुंच गई। सुरेंद्र पांचवीं का स्टूडेंट है। पिता हरिराम ड्राइवर हैं।

बांगड़ हॉस्पिटल के सर्जन मनीष चौधरी ने बताया कि बच्चा करीब 30 तक झुलसा है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है।

मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह का निरीक्षण किया



जालोर के पास आहोर में स्थित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में मेडिकल स्टोर का निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश अहसान अहमद ने किया। फोटो-राष्ट्रदूत

जालोर, (कासं)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हारून के निदेशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अहसान अहमद ने गुरुवार को आहोर स्थित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बालकों के रहने

के कक्षा का निरीक्षण किया। मेडिकल स्टोर रूम का भी निरीक्षण कर निर्देश दिए कि दवाओं के अवधि की लिथि समय समय पर देखकर अवधि पार दवाइयों को अलग रखा जावे। उन्होंने रसोई घर का भी निरीक्षण किया और भोजन बनाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि यहां पर रहने वाले विमंदित बालकों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाए।

उन्होंने कहा कि ये सभी बालक विशेष श्रेणी के हैं इसलिए इनके स्वास्थ्य की समय समय पर योग्य चिकित्सकों से आवश्यक रूप से जांच करावाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बालकों को दी जाने वाली दवाइयों चिकित्सकों के निर्देशानुसार समय पर दी जावे। इस दौरान उन्होंने बालकों के खान पान का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए इनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जावे।

पाली में सुभाष सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित



पाली में भाजपा के महाराणा प्रताप मंडल के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन स्थित सुभाष सर्किल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। फोटो-राष्ट्रदूत

पाली, (नि.सं.)। भाजपा के महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले "नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी" जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप

मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित सुभाष सर्किल पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक जयंती मनाई। पूर्व विधायक ज्ञानचंद्र पारख, पूर्व सभापति महेन्द्र बोहरा, भाजपा जिला महामंत्री सुनील भंडारी, पूर्व उप

सभापति ललित प्रीतमानि एवं मूलसिंह भाटी, पार्षद ओमप्रकाश स्वामी, जिला महामंत्री मोर्चा सुरेश भोल, लक्की शर्मा, सुरेश खिंची, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रितिक बंजारा, आशीष तिवारी, श्याम बंजारा आदि मौजूद रहे।

युवक ने की आत्महत्या

रेवदर, (नि.सं.)। रेवदर क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मजदूरी करता था।

मृतक की पहचान बाड़मेर के गोडा निवासी मुल्लान के रूप में हुई है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। मृतक के चाचा पप्पूराम भोल ने बताया कि वह पिछले 4-5 महीने से नंदगांव गौशाला में मजदूरी कर रहा था। उसका भतीजा मुल्लान भी उसके साथ काम करता था और छात्रावास में रहता था। बुधवार रात करीब 12 बजे दोनों कमरा नंबर 11 में सो गए। सुबह साढ़े सात बजे पप्पूराम उठा तो मुल्लान कमरे में नहीं था। तलाशी के दौरान पास के कमरा नंबर 12 का दरवाजा खुला मिला, जहां मुल्लान का शव छत के लोहे के ढंगल से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। सूचना ने शव को रेवदर अस्पताल की मॉर्चरूम में रखवाया। गुरुवार शाम को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

संपत्ति विवाद को लेकर परिवार के लोग भिड़े

जोधपुर, (कासं)। शहर के पावटा चौराहा के समीप तुहार कॉलोनी में दोपहर में संपत्ति विवाद के चलते एक ही परिवार के कुछ लोग झगड़ पड़े। परिवार में झगड़े के साथ मातृपेट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर 12 लोगों को शांतिभंग में हिरासत में लिया। विवाद एक दुकान को लेकर बताया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज होने पर अग्रिम पड़ताल आरंभ कर पाएगी। पुलिस ने बताया कि पावटा पुलिस चौकी के समीप तुहार कॉलोनी आई हुई है। यहां पर एक दुकान को लेकर एक ही परिवार के लोगों में विवाद चल रहा है। दोपहर में परिवार के लोग आसपस में उलझते हुए झगड़ा करने लगे। दुकान पर तोड़फोड़ की गई।

पिकअप की टक्कर से शिक्षिका की मौत

जोधपुर, (कासं)। फलोदी में गुरुवार सुबह एक पिकअप ने एक्टिवा स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर से वह सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने

उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार एक्टिवा से रोजाना की तरह उदाणियों की ढाणी निवासी टीचर बसंत पंवार (23) सांखरी सरकारी स्कूल जा रही थीं। रास्ते में एक तेज रफार से आई दूध परिवहन करने वाली पिकअप

ने उसकी एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर घायल हो गईं। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिजनों की शिकायत पर पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

बाला साहेब जयंती पर भगवा रैली निकाली



पाली में बाला साहेब शिवसेना शिंदे पार्टी ने भगवा रैली निकाली। फोटो-राष्ट्रदूत

पाली, (नि.सं.)। बाला साहेब शिवसेना शिंदे पार्टी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालासाहेब ठाकरे जन्म जयंती के अवसर पर जिला अध्यक्ष तखत सिंह सोलंकी के नेतृत्व में विशाल भगवा रैली निकाली गई।

रैली हृदय स्थल शिवाजी सर्कल से बैंड नवकार दरवार व किना डायमन बैंड डिजे की मधुर धुनों से रवाना होकर जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाते हुए हाथ में केसरिया ध्वज उठाकर शहर के मुख्य मार्गों व बाजार में पिंढू भाई आहुजा द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए गीता भवन में संपन्न हुई।

इस मौके पर विक्रम तेजी, मगराज पादरली, महेंद्र माडा, रमेश बंजारा, उदय शेट्टी, मनोज गर्ग, सुरेंद्र सिंह कानंदरा, राजसा मानपुरा रवसा देवड़ा, बालू भाई अकेली, प्रवीण सिंह इन्दा, अर्जुन, टाडगर, राजेश वैष्णव, मातृशक्ति के रूप में ललिता गाडोलिया लाहौर, अनिता सिंह सिंगार, ललिता पंवार, मंजू जैन, कविता पंवार, अनिता गाडोलिया, लता वैष्णव, रुचिका शर्मा, चंद्रिकाशर्मा, शांति शर्मा, सरोज राठी, हर्षिता चारोटिया, खुशुब, किरण सोलंकी, अरुणा, दिवसीका शर्मा, निशा डाबी, टीना डाबी, शिवसेना जिला पदाधिकारी मातृशक्ति व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इस मौके पर विक्रम तेजी, मगराज

